पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं.541

लखीसराय थाना कांड संख्या-565 वर्ष-2009, जिला-लखीसराय से उद्भूत

=====

उदय यादव, पुत्र-अर्जुन यादव, निवासी, ग्राम-लखोचक, पुलिस थाना-चनान, जिला-
लखीसराय।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति

अपीलार्थी/ के लिए : श्री यागेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

=====

- विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) एवं अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता - अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज करने में पाँच दिनों की देरी, जिसके लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न करती है। (आधारित: नंद लाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2023 (10) एससीसी 470)-हितग्रहीत गवाह एवं भूमि विवाद - विरोधाभासी गवाहियाँ एवं प्रक्रियागत त्रुटियाँ- वैज्ञानिक साक्ष्य एवं फोरेंसिक कमी (संदर्भित: तोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 (7) एससीसी 178)-प्रत्यक्षदर्शी गवाही अस्वीकृत - अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया- त्रुटिपूर्ण जाँच पर दृष्टांत - केवल अनुमान या जाँच की प्रक्रियागत कमियों के

आधार पर दोषसिद्धि संभव नहीं। अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए स्वतंत्र पुष्टिकरण आवश्यक है
- दोषसिद्धि निरस्त।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

तिथि:- 03-05-2024

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगेश चंद्र वर्मा और राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना गया।

2. वर्तमान अपील अपीलकर्ता-दोषी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें लखीसराय थाना कांड संख्या 565/2009 जी.आर. केस संख्या 1226/2009 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 494 ए/2011/परीक्षण संख्या 326/2018 में विद्वान त्वरित न्यायालय-II, व्यवहार न्यायालय, लखीसराय द्वारा दिनांक 03.05.2019 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी गई है। जिसके तहत संबंधित ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 और 365 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत आजीवन कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतने का निर्देश दिया है और

जुर्माना जमा न करने की स्थिति में उसे एक महीने की साधारण कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत पांच साल के लिए कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर पंद्रह दिन की साधारण कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत पांच साल के लिए कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर पंद्रह दिन की साधारण कारावास भुगतनी होगी। सभी सजाएं। हालांकि, सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला, जैसा कि सूचक मनोहर साव, पीडब्लू-8 द्वारा लिखित सूचना के माध्यम से बताया गया है, जो 08.11.2009 को पुलिस अधीक्षक, लखीसराय को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे सोनू कुमार, उम्र लगभग नौ (9) वर्ष का 04.11.2009 को लगभग 9:00 बजे गाँव लाखोचक, डाकघर बिछवाई, थाना इटौन, जिला लखीसराय से अपहरण कर लिया गया था। वर्णन में उसके विवरण के बारे में भी बताया गया है अपहृत पुत्र के शरीर के रंग और पहचान के निशान के संबंध में, जिसमें दाहिने पैर की आंख के नीचे चोट का निशान है, वह काले रंग का फुल पैंट और सफेद हाफ शर्ट पहने हुए था। लिखित सूचना से यह भी पता चलता है कि उन्हें 07.11.2009 को मोबाइल नंबर 9504963018 से 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये की फिरोती के लिए कॉल आया था, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्हें दृढ़ संदेह है कि उनके बेटे सोनू कुमार को हरिकिशन यादव, शशि भूषण यादव, लक्ष्मी यादव और संतोष यादव, सभी स्वर्गीय विजय यादव उर्फ झूना यादव के पुत्रों द्वारा अपहरण और हत्या कर दी जा सकती है क्योंकि उनके साथ जमीन का विवाद है।

4. उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर, लखीसराय (चानन) 2009 का कांड संख्या 565 दिनांक 09.11.2009 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363-ए/34 के अंतर्गत

अपराध के लिए पंजीकृत किया गया, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर जांच के पश्चात नामित अभियुक्तों तथा अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान क्षेत्राधिकारी दंडाधिकारी ने निम्नलिखित का अनुपालन करने के पश्चात आ.दं.सं. की धारा 207 के तहत आरोपी-अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 363, 364 और 365 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और मामले को आ.दं.सं. की धारा 209 के तहत सुनवाई और निपटान के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

5. विद्वान निचली अदालत ने अभिलेख प्राप्त करने के बाद इस मामले को सत्र सुनवाई संख्या 494/2011 के रूप में सुनवाई के लिए पंजीकृत किया और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपी-अपीलकर्ता सहित सभी आठ आरोपियों के खिलाफ भा.दं.सं की धारा 363, 364 और 365 के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किए, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और खुद को दोषी नहीं बताया। अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा दावा किए जाने के परिणामस्वरूप, यह मुकदमा शुरू किया गया।

6. इस समय, यह उल्लेख करना उचित होगा कि मूल सत्र परीक्षण संख्या 494/2011, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आठ अभियुक्तों में से एक दिनेश कुमार यादव को किशोर पाया गया और उसके मामले को तदनुसार अलग कर दिया गया। अभियुक्त उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) और सुधीर यादव फैसले के चरण में फरार हो गए, जिसके परिणामस्वरूप, उनके मामले को अलग कर दिया गया, जहां अपीलकर्ता/अभियुक्त के मुकदमे को एस.टी. संख्या 494 ए/2011 के रूप में पुनः क्रमांकित

किया गया, जहां उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 364(ए), 363 और 365 के तहत अपराधों के लिए दोषी पाया गया।

7. अभियोजन पक्ष ने विद्वान निचली अदालत के समक्ष अपना मामला स्थापित करने के लिए कुल दस (10) गवाहों की जांच की, जो पीडब्लू-1 राजीव कुमार साव; पीडब्लू-2 सुदामा कुमार; पीडब्लू-3 राम रजक; पीडब्लू-4 साबो देवी; पीडब्लू-5 डबलू महतो; पीडब्लू-6 पिकी देवी; पीडब्लू-7 पुतुल देवी; पीडब्लू-8 मनोहर साव; पीडब्लू-9 सोहन महतो और पीडब्लू-10 अतुल कुमार मिश्रा (इस मामले के जांच अधिकारी) हैं।

8. उपरोक्त के अलावा, एक गवाह संजीव कुमार, की अदालत द्वारा पीडब्लू-1 के रूप में जांच की गई है।

9. अभियोजन पक्ष ने मामले के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार हैं:

प्रदर्श '1' लिखित रिपोर्ट पर सूचक मनोहर साव के हस्ताक्षर;

प्रदर्श '2' प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के संबंध में समर्थन और हस्ताक्षर;
और

प्रदर्श 'I' मोबाइल नंबर 9631146123.

10. बचाव पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान अपने मामले के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

11. मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आ.दं.सं की धारा 313 के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार अपीलकर्ता-अभियुक्त के

समक्ष वे सभी अभियोगात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें उसने उन सभी परिस्थितियों और साक्ष्यों को नकारते हुए अस्वीकार कर दिया, जो उसे बताए गए थे और अपनी बेगुनाही का दावा करके झूठे आरोप लगाने के बारे में कहा था।

12. मुकदमे के दौरान सामने आई सामग्री के आधार पर और पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।।

13. दोषसिद्धि और सजा के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।।

14. इसलिए, अपील।

अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से तर्क

15. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगेश चंद्र वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है- अभियुक्त ने कहा कि अपीलकर्ता का नाम शुरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, बल्कि उसका नाम पिछली दुश्मनी के कारण जांच के दौरान आया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मुकदमे के दौरान मुखबिर के बयान में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सुधार हुआ है। यह कहा गया है कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि मुखबिर को फिरौती के लिए कॉल मिली थी, वह अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा बिना किसी पुष्टिकरण साक्ष्य के की गई थी, उसे मामले में दोषी ठहराया गया।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मुखबिर अर्थात् मनोहर साव (पीडब्लू-8) ने खुद को घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है और अपने मुख्य परीक्षण में विशेष रूप से कहा है कि कैसे उसके बेटे अर्थात् सोनू कुमार को अभियुक्तों

द्वारा अपहरण किया गया था। यह कहा गया है कि मुखबिर ने विशेष रूप से कहा कि सह-अभियुक्त भूषण यादव और संतोष यादव उसके बेटे को मोटरसाइकिल से ले गए, जबकि उसके बेटे को सह-अभियुक्त भूषण यादव ने पकड़ रखा था, जबकि संतोष यादव और राजेश यादव दूसरी मोटरसाइकिल पर थे। यह बताया गया है कि यदि ऐसा था, तो मुखबिर की यह गवाही स्पष्ट रूप से सुझाव देती है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना 04.11.2009 की है, जहां पीड़ित नाबालिग लड़के के पिता के अलावा कोई भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के बजाय तुरंत, सूचना देने वाले ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाकर खुद को इतने दिनों तक प्रतीक्षा मोड में रखा, जिससे पूरी बात संदिग्ध हो गई क्योंकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन यह मामला 09.11.2009 को यानी घटना के पांच दिन बाद दर्ज किया गया।

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि मुखबिर ने बताया कि उसके मोबाइल नंबर 9631146123 पर मोबाइल नंबर 9504963018 से 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए कॉल आई थी, जिसे उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) और सुधीर यादव ने किया था। यदि ऐसा है, तो अपीलार्थी-आरोपी का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कहा गया है कि इसे दर्ज करने के समय तक उसे उक्त मोबाइल नंबर से फिरौती के लिए कॉल आ चुकी थी, लेकिन उसने सुनवाई के दौरान अपने बयान में सुधार किया और अपीलार्थी-आरोपी को फंसाया, जो निर्दोष है।

18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस मोबाइल नंबर पर फिरौती की कॉल की गई थी, वह भी इस अपीलार्थी-अभियुक्त की नहीं है। यह बताया गया है कि कोई कॉल विवरण रिपोर्ट (संक्षेप में 'सीडीआर') नहीं है, कोई फॉरेंसिक जांच नहीं है, कोई वॉयस

सैंपलिंग नहीं है और यहां तक कि जांच के दौरान जारी मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया था, जिसके माध्यम से कॉल किया गया था, जिससे पूरे आरोप प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है। यह सुझाव देते हुए कि केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर, अपीलकर्ता-अभियुक्त को प्रश्नगत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सूचक (पीडब्लू-8) द्वारा उनके अपहृत पुत्र सोनू कुमार और उनके बहनोई गौतम कुमार के बारे में तलाशी ली गई थी, जिनसे मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी।

19. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सूचना देने वाले (पीडब्लू-8) ने घटना के तुरंत बाद, जब उसे पता चला कि उसके पुत्र को आरोपी व्यक्ति भूषण यादव और संतोष यादव ले जा रहे हैं, तो उसने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया, लेकिन जब वह उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सका, तो वह अपने घर वापस आ गया और उसके बाद अपने भाई राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1), पीड़ित की दादी (पीडब्लू-4), उसकी पत्नी (पीडब्लू-6) और उसके छोटे भाई (पीडब्लू-7) की पत्नी और एक गौतम कुमार, जिनसे मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की गई थी, जो स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि ये अभियोजन पक्ष के गवाह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, लेकिन मुकदमे के दौरान उन्होंने घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। अभियोजन पक्ष इन अंतर्विरोधों/सुधारों की व्याख्या करने में विफल रहा, जिसे विद्वान निचली अदालत ने अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराते समय पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया। इस संदर्भ में, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के जांच अधिकारी होने के नाते पीडब्लू-10 ने विशेष रूप से मुकदमे के दौरान कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी ने भी जांच के दौरान घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा नहीं किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एस. टी. सं. 494/2011 के दोषियों को पहले ही माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा सी. आर. के माध्यम से बरी कर दिया गया था। अपील (खं.पी.) सं. 960/2013, आ. अपील (खं.पी.) सं. 1082/2013 और आ. अपील (खं.पी.) सं. 71/2014, साक्ष्य के लगभग एक ही सेट के साथ और 'समानता' के इस तरह के सिद्धांत के रूप में भी अपीलार्थी/अभियुक्त का पक्ष लेते हैं।

20. विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने तर्क को समाप्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्टों पर भरोसा किया। राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक बनाम सरवनन और एक अन्य [(2008) 17 एस. सी. सी. 587]; नंद लाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [(2023) 10 एस. सी. सी. 470]; संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, कृष्णागिरी [(2012) 4 एस. सी. सी. 124]; तोमासो ब्रूनो और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2015) 7 एस. सी. सी. 178]।

21. श्री सुजीत कुमार सिंह, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक राज्य की ओर से उपस्थित होते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में सूचक एक अशिक्षित व्यक्ति है और उसे कानून के तकनीकी पहलू की जानकारी नहीं है, इसलिए मुकदमे के दौरान छोटी-मोटी विसंगतियां सामने आ ही जाती हैं, जो न्याय प्रदान करने में बाधा नहीं बनेगी। यह बताया गया कि जहां तक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में देरी के बारे में दलील का सवाल है, सूचक की गवाही से यह स्पष्ट है कि पहले वह घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन मना करने पर वह पुलिस अधीक्षक लखीसराय के पास गया, जबकि इस बीच उसने अपने स्तर पर भी परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने अपहृत बेटे की तलाश की।

22. राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अन्य सह-अभियुक्तों को बरी किए जाने का वर्तमान मामले की योग्यता

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अभियुक्त/अपीलकर्ता का मुकदमा अलग-अलग था, जहाँ आरोप की प्रकृति भी भिन्न प्रतीत हो रही है, जो इस अपीलकर्ता-अभियुक्त के लिए अपराध-सिद्ध है, क्योंकि उसने फिरोती के लिए कॉल किया था।

23. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के मद्देनजर, पीड़ित लड़के अर्थात् सोनू कुमार की तलाश में उसके साथ आए मुखबिर के साले की जांच न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में अपीलीय चरण में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

24. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुनः- वर्तमान अपील के न्यायोचित एवं उचित निर्णय के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार हैं:-

25. पी.डब्ल्यू.-8 मनोहर साव, जो इस मामले के सूचक हैं तथा पीड़ित बालक सोनू कुमार, उम्र लगभग 9 वर्ष, के पिता हैं। उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि घटना दिनांक 04.11.2009 की है तथा रात्रि के 9:00 बजे थे। उन्होंने बयान दिया है कि उस समय पुस्तकालय के पास साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा था, जहां उनका पुत्र भी उक्त साइकिल रेस देखने के लिए मौजूद था, जो रात्रि 9:30 बजे समाप्त हो गई। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि साइकिल रेस के बाद जब वे अपने घर लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र सोनू कुमार को सह-अभियुक्त भूषण यादव एवं संतोष यादव

मोटरसाइकिल पर ले गए, जहां उन्हें भूषण यादव ने पकड़ लिया तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर सह-अभियुक्त संतोष यादव एवं राजेश यादव थे। वे जंगल की ओर चले गए। उसने यह भी बताया कि उसने उनका पीछा किया लेकिन जब वे नज़रों से ओझल हो गए तो वह घर वापस आया और अपने भाई राजीव कुमार (पीडब्लू-1), दादी (पीडब्लू-4), पत्नी (पीडब्लू-6) और अपने साले गौतम कुमार (जिसकी जांच नहीं की गई) को पूरी घटना बताई। आगे यह भी बताया गया कि उन्होंने फिर से सोनू की तलाश की। कुमार से मिलने गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका और अंततः रात में ही उसके पास वापस आ गया। अगली सुबह, वह अपने भाई राजीव कुमार साव (पी.डब्लू.-1) के साथ पुलिस स्टेशन गया और थाना इंचार्ज को घटना बताई, जिन्होंने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि पहले वे स्वयं गहन खोज करें और फिर आएं। महीने की 7 तारीख को, वह पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पास गया, जहाँ उसने अपना बयान दिया, जिसे पुलिस अधीक्षक लखीसराय ने लिखा था। उसने यह भी गवाही दी कि सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलकर्ता-अभियुक्त) द्वारा उसके मोबाइल फोन पर 5 लाख रुपये की फिरौती माँगी गई थी, जो उसके मोबाइल नंबर 9504963018 से उसके मोबाइल नंबर 9631146123 पर की गई थी। उसने उक्त ऑडियो कॉल रिकॉर्ड की थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फिरौती के लिए की गई कॉल के बारे में भी बताया और उनके सामने रिकॉर्ड की गई ऑडियो कॉल भी सुनाई। उन्होंने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान के बाद प्रदर्श '1' के रूप में प्रदर्शित हुआ। उन्होंने पुलिस इंचार्ज के सामने फिरौती के बारे में ऑडियो कॉल रिकॉर्ड भी सुनाया। उन्होंने उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) और सुधीर यादव से इस डर से संपर्क नहीं किया कि वे उन्हें बंधक बना लेंगे। उनका लगभग नौ साल का बेटा आज तक बरामद नहीं हुआ। अखबार से पता चला कि उसके बेटे की हत्या

कर दी गई है और उसका शव गंगा नदी में फेंक दिया गया है। उसने न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता-आरोपी की पहचान की।

25.1 जिरह के दौरान उसने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल काले रंग की थी और उसने गौतम कुमार (जिसकी जांच नहीं की गई) के साथ अपने बेटे की तलाश शुरू की, जो घटना के दो दिन पहले उसके साथ था। उसने बताया कि वह 7वें दिन पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पास गया था, जबकि घटना चार तारीख की है। वह अभियुक्तों के डर से किसी के पास नहीं गया। वह पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पास तभी गया जब उसे फिरौती के लिए कॉल आया। बताया गया कि वह उसका मोबाइल था, लेकिन सिम कार्ड राजीव कुमार साव (पी.डब्लू.-1) के नाम पर था। उसने बताया कि जब वह पुलिस अधीक्षक लखीसराय को बयान दे रहा था, तो उसके चाचा उदय साव (जिसकी जांच नहीं की गई) भी वहां मौजूद थे। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक ने अपने बयान में अपने चाचा को गवाह नहीं बनाया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज़मीन विवाद के बारे में कुछ नहीं बताया। आगे की जिरह में उन्होंने कहा कि लिखित सूचना उनके सामने नहीं लिखी गई थी और उन्हें यह भी नहीं पता कि इसे किसने लिखा है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय, मोबाइल उसके पास था। यह कहा गया कि उसका बयान पुलिस प्रभारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने के बाद महीने की 9 तारीख को दर्ज किया गया था और उसी दिन उसकी मां (पी.डब्लू.-3), भाई (पी.डब्लू.-1) और अन्य पांच व्यक्तियों का बयान दर्ज किया गया था। उसने कहा कि साइकिल रेस में लगभग 200 लोग मौजूद थे। उसका बेटा सोनू कुमार अपने दोस्तों सुदामा (पी.डब्लू.-2) और संदीप कुमार (जिनकी जांच नहीं की गई) के साथ लगभग 6:30 बजे साइकिल रेस देखने आया था। उनका सुदामा और संदीप कुमार से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने पुलिस के सामने यह बयान दिया था कि उसने देखा कि उसके बेटे को सोनू कुमार

की मोटरसाइकिल पर ले जाया गया था। उसे मोबाइल नंबर 9504963018 से 25 लाख रुपये की फिरौती के लिए कॉल आया था। 5 लाख रुपये, जिसे उन्होंने अभिलेख किया था। उक्त रिकॉर्डेड ऑडियो को पुलिस अधीक्षक के समक्ष चलाया गया, लेकिन उन्होंने इसे जब्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल उनके नाम पर नहीं था, बल्कि यह राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) के नाम पर था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष जो बयान दिया, वही बयान उन्होंने पुलिस अधीक्षक लखीसराय के समक्ष दिया था। उन्होंने कहा कि बयान की विषय-वस्तु पुलिस अधीक्षक लखीसराय द्वारा उन्हें पढ़कर नहीं सुनाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष दिए गए बयान को उनके वकील ने पढ़ा, जिन्होंने इस मामले में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक लखीसराय के समक्ष बयान दिया कि उन्हें मोबाइल नंबर 9631146123 पर कॉल आया, जो उन्हें घटना के तीन दिन बाद मिला। यह कहा गया कि पुलिस द्वारा मोबाइल का प्रिंटआउट नहीं लिया गया और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अपीलकर्ता द्वारा उन्हें 5 लाख रुपये की फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं किया गया था और उन्होंने साजिश के तहत अपीलकर्ता-आरोपी को झूठा फंसाया।

26. पी.डब्लू.-1 राजीव कुमार है, जो सूचक (पी.डब्लू.-8) का भाई है, जिसने घटना की तारीख और समय का समर्थन किया। उन्होंने अपहरण का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया और कहा कि जब उनका भतीजा सोनू कुमार (पीड़ित) उनके पास वापस आ रहा था, तो उसे हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, विकास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव और राजेश यादव ने पकड़ लिया। उसके दोस्त सुदामा कुमार और संतोष कुमार ने शोर मचाया। यह गवाही दी गई कि पीड़ित को सह-आरोपी भूषण यादव और राजेश यादव ने ले लिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप

से कहा कि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने यह बयान दिया कि 4-5 दिनों के बाद उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) और सुधीर यादव द्वारा मोबाइल कॉल किया गया और उनके भाई मनोहर साव (सूचनाकर्ता/पी.डब्लू.-8) से 4 से 5 लाख रुपये की फिरोती मांगी गई। उनके भतीजे का आज तक पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि घटना के चार दिनों के बाद पुलिस अधीक्षक, लखीसराय को सूचना दी गई। उन्होंने यह बयान दिया कि अभियुक्तों ने पैसे के लालच में यह अपराध किया और अभी भी वे इस मामले में गवाही न देने की धमकी दे रहे हैं।

26.1. जिरह करने पर उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी घटना के 4-5 दिनों के बाद उनके गांव आए और उनसे घटना के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि घटना के चार दिन बाद उनके भाई (पीडब्लू-8) लखीसराय के पुलिस उपाधीक्षक को सूचना देने गए थे, लेकिन वह उनके साथ नहीं थे। उन्होंने ट्रायल के दौरान यह भी बयान दिया कि उन्होंने जांच अधिकारी को बताया कि घटना की तारीख और समय पर वह अपने भतीजे सोनू कुमार और गौतम कुमार के साथ थे। सूचनाकर्ता/पीडब्लू-8 का भाई। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष यह बयान दिया था कि उनके भतीजे को हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, विकास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव और राजेश्वर यादव ने पकड़ रखा था। उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष यह बयान दिया कि उनके भतीजे सोनू कुमार और उनके दोस्त सुदामा कुमार और संतोष कुमार ने शोर मचाया था। उन्होंने कहा कि रात का अंधेरा था, लेकिन घटनास्थल पर एक भी बिजली का बल्ब नहीं जल रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपी दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान में उनके साथ तीन आरोपी भी थे, लेकिन उस समय तक उन्हें अपराध में अपनी संलिप्तता के बारे में पता नहीं था, जिसका खुलासा दिनेश यादव की गिरफ्तारी के बाद ही हुआ। उन्होंने बताया

कि घटना के तुरंत बाद उनके भाई (पीडब्लू-8) ने पुलिस स्टेशन को फोन नहीं किया, बल्कि अगली सुबह 10:00 से 11:00 बजे के बीच चानन पुलिस स्टेशन को फोन किया। उन्होंने बताया कि वे उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स का प्रिंटआउट पेश कर सकते हैं, जिससे 4 से 5 लाख रुपये की फिरोती मांगी गई थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस आशंका के तहत कि आरोपी व्यक्तियों ने उसके भतीजे की हत्या की होगी, उक्त फोन प्रिंट को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। वह मोटरसाइकिल के मेक के बारे में बताने में विफल रहा। वह मोटरसाइकिल के रंग के बारे में भी बताने में विफल रहा। यह कहा गया कि उसे सह-आरोपी दिनेश यादव की गिरफ्तारी के बाद ही अपीलकर्ता-आरोपी की संलिप्तता के बारे में पता चला। वह साइकिल रिस देखते समय सह-आरोपी दिनेश यादव को नहीं देख सका।

27. पीडब्लू-2 सुदामा कुमार है और वह पीडित सोनू कुमार का मित्र था और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार उसके अपहरण के दौरान उसके साथ मौजूद था, और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हुए सुनवाई के दौरान अलार्म बजाया और वह मुकर गया। राज्य की ओर से उसकी जिरह में कुछ भी ठोस नहीं दिखाई देता है, जिसका उपयोग अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के संबंध में पुष्टि/विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है, जिन्होंने घटना का समर्थन किया।

27.1 जिरह के दौरान उसने बताया कि उसने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से गवाही दी थी और उसने सोनू कुमार (पीडित) को मेले में नहीं देखा था।

28. पी.डब्लू-3 राम रजक है, जिसने बयान नहीं दिया अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही होने पर भी न्यायालय में उससे कुछ प्रश्न पूछे गए, जिन्होंने कहा कि वह मेला देखने नहीं गया था तथा पुलिस के समक्ष कोई बयान भी नहीं दिया।

29. पीडब्लू-4 साबो देवी है, जो पीड़ित सोनू कुमार की दादी है, जिसने घटना की तिथि तथा समय का भी समर्थन किया, तथा अपहरण की कथित घटना में हरकिशन यादव, भूषण यादव, लक्ष्मी यादव तथा संतोष यादव की संलिप्तता के बारे में गवाही दी। उसने अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग का भी समर्थन किया।

29.1. अपीलकर्ता-आरोपी उदय यादव की ओर से जिरह करने पर उसने बताया कि रात हो चुकी थी तथा वह अपने घर पर थी। शेष अभियुक्तों की ओर से जिरह करने पर उसने बताया कि घटना से पूर्व अभियुक्तों के साथ उसके शत्रुतापूर्ण संबंध थे। उसने विशेष रूप से बताया कि वह चश्मे की सहायता के बिना नहीं देख सकती थी। उसे घटना के बारे में पड़ोसी से पता चला, जब वह सोहन महतो के बाहरी आंगन में थी।

30. पीडब्लू-5 डबलू महतो है, जिसने इसका समर्थन नहीं किया अभियोजन पक्ष के मामले में पक्षद्रोही हो गया। राज्य द्वारा अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के साथ पुष्टि/विरोधाभास के उद्देश्य से की गई जिरह में उसके द्वारा दिए गए बयान में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया, जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है।

31. पी.डब्लू.-6, पीड़ित की मां और पी.डब्लू.-8/सूचनाकर्ता की पत्नी है, जिसने घटना की तारीख और समय का समर्थन किया और यह गवाही दी कि उसके बेटे का अपहरण हरकिशन यादव, भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), बिलास यादव, सुधीर यादव ने किया था। इस स्तर पर, विद्वान अभियोजक द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि क्या उसने इन व्यक्तियों को उसके बेटे को ले जाते हुए देखा था? जिसके उत्तर में उसने 'हां' कहा। इसके बाद, इस प्रश्न को प्रमुख प्रश्न होने के कारण अनुमति नहीं दी गई। उसने बयान दिया कि गौतम

कुमार (जिसकी जांच नहीं की गई) और उसके पति (मुखबिर/पीडब्लू-8) ने उसे सोनू कुमार के अपहरण के बारे में सूचना दी और तभी उसे घटना के बारे में पता चला। इसके बाद, उक्त सूचना पर, वह पुस्तकालय के पास आई और देखा कि आरोपी व्यक्ति दक्षिण-पूर्व दिशा में जा रहा था। यह बयान दिया गया कि चार दिनों के बाद, उसके पति (पीडब्लू-8) के मोबाइल पर 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी।

31.1. जिरह करने पर, उसने कहा कि घटना के दस मिनट बाद, गौतम कुमार और उसके पति मनोहर साव (पीडब्लू-8) घर आए, उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। यह कहा गया कि एक से दो मिनट के तुरंत बाद उसके पति और गौतम चले गए, और दस मिनट के बाद, वह पुस्तकालय (घटना स्थल) के पास आई, जहाँ उसकी मुलाकात पाँच व्यक्तियों से हुई, जो सह-ग्रामीण थे, लेकिन उसे उनका नाम याद नहीं था। उसने कहा कि वह सह-ग्रामीणों की मदद से आरोपियों का पीछा नहीं कर सकी। यह कहा गया कि तीन सह-आरोपी व्यक्ति मोटरसाइकिल पर थे। वह उस मोबाइल फोन का नंबर नहीं बता सकी जिस पर फिरौती के लिए कॉल किया गया था। उसने कहा कि मोटरसाइकिल का रंग काला था। वह उन व्यक्तियों के नाम नहीं बता सकीं, जिन्होंने मोटरसाइकिल पर सोनू कुमार को पकड़ा था, क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था।

32. पीडब्लू-7 पुतुल देवी है, जो मुखबिर की मां है/पीडब्लू-8 ने घटना की तारीख और समय का समर्थन किया घटना की सूचना दी तथा बताया कि उस समय वह अपने घर पर थी। उसने हरकिशन यादव, भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, विकास यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, सुधीर यादव, उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) का नाम लिया तथा बताया कि उन्होंने सोनू कुमार का अपहरण पुस्तकालय के पास से किया है। उसे यह तथ्य गौतम कुमार (जिसकी जांच नहीं की गई) से पता चला। वह पुस्तकालय

गई, जहां उसे पता चला कि स्कूटर पर तीन व्यक्ति सवार थे। उसने बताया कि 07.11.2009 को सह-आरोपी भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, उदय यादव, राजेश यादव, सुधीर यादव तथा उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) उसके घर आए तथा 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी, ऐसा न करने पर उन्होंने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। बताया कि इससे पहले पी.डब्लू.-8 के मोबाइल पर भी फिरौती के लिए कॉल किया गया था। बताया गया कि चूंकि बच्चा वापस नहीं किया गया, इसलिए आरोपियों को 5 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया।

32.1. जिरह के दौरान यह कहा गया कि उसने बताया कि गौतम कुमार उसकी भाभी (पीडब्लू-6 पिकी देवी) का भाई है। उसने बताया कि गौतम कुमार उसी दिन दोपहर करीब 3:00 बजे साइकिल रेस देखने आया था। बताया गया कि फिरौती की मांग पहली बार की गई थी। सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) द्वारा घर पर की गई मांग, पहली बार भूषण यादव द्वारा की गई थी। घटना के चार दिन बाद उसने पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया। उसने पुलिस के समक्ष अपने पड़ोसी हरकिशन यादव, भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव के साथ भूमि विवाद के बारे में बताया। यह कहा गया कि फोन कॉल 06.11.2009 को सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) द्वारा किया गया था। उसे घटना के बारे में सुबह 9:00 बजे गौतम कुमार से पता चला और उस समय तक उसकी सास (पीडब्लू-4), गोतनी (ननद) पिकी देवी (पीडब्लू-6), और राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) वहां मौजूद थे और उनके अलावा वहां कोई नहीं था। बताया गया कि वह पिकी देवी (पीडब्लू-6) और उसके पति राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) के साथ घटनास्थल पर गई थी। उसकी सास (पीडब्लू-4) बच्चों के साथ घर पर ही रहती है। उससे न्यायालय में सवाल पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए उसने बताया कि फिरौती

के लिए फोन पर और घर पर भी कॉल आने के बाद पुलिस को तत्काल कोई सूचना नहीं दी गई।

33. पी.डब्लू.-9 सोहन महतो है, जो मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलट गया और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। राज्य की ओर से उनके द्वारा की गई जिरह के दौरान कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया, जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की गवाही के साथ पुष्टि/विरोधाभास के लिए किया जा सके, जिन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया।

34. पी.डब्लू.-10 इस मामले के जांच अधिकारी हैं, जिनका नाम अतुल कुमार मिश्रा है। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया कि 04.11.2009 को वे चानन पुलिस स्टेशन के प्रभारी थे और वहीं पर पदस्थापित थे। उन्हें 18.11.2009 को पुलिस अधीक्षक लखीसराय के कार्यालय से एक पत्र मिला, जो इस मामले के सूचक मनोहर साव (पी.डब्लू.-8) द्वारा दिया गया था और उक्त सूचना के आधार पर उन्होंने औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की और जांच अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालते हुए जांच शुरू की। उन्होंने औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के लिए अग्रेषित करने के संबंध में लिखित सूचना और अपने प्रारंभिक हस्ताक्षर की पहचान की। जिसे उन्होंने अदालत के समक्ष पहचाना और उनकी पहचान पर, इसे प्रदर्श '2' के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने यह गवाही दी कि 10.11.2009 को, उन्होंने संजीव कुमार नामक व्यक्ति का धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया। दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'आ.दं.सं.') जिसका मोबाइल नंबर फिरौती के लिए कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और वही मोबाइल नंबर 9504963018 से मोबाइल नंबर 9631146123 पर किया गया था, जिसे रिकॉर्ड किया गया और उसके

सामने प्रदर्शित किया गया। उसने मोबाइल नंबर 9631146123 की पहचान की और पहचान करने पर, इसे परीक्षण के दौरान सामग्री **प्रदर्शनी संख्या 1 (आपत्ति के साथ)** के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित अभी भी लापता है और दिनेश यादव (सह-अभियुक्त) ने गिरफ्तारी के बाद अपने इकबालिया बयान के माध्यम से कहा कि अपहरण के 4-5 वें दिन के बाद उन्होंने अपहृत बच्चे की '*बरहिया ताल*' के पास हत्या कर दी थी और आरोपियों की संलिप्तता के बारे में भी कबूल किया था।

34.1. जिरह करने पर, उसने कहा कि जांच के दौरान उसने मोबाइल जब्त नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उस मोबाइल को चिन्हित नहीं किया, जिसे मुखबिर ने उनके सामने पेश किया था, ताकि अदालत के सामने उसकी पहचान की जा सके। उन्होंने दोनों मोबाइलों के बारे में जांच के दौरान कॉल डिटेल् रिपोर्ट (सीडीआर) का प्रिंट आउट नहीं लिया। यह कहा गया कि इस मामले में कोई मोबाइल जब्त नहीं किया गया और न ही कोई कॉल डिटेल् रिपोर्ट (सीडीआर) प्राप्त की गई। जिरह के दौरान, उन्होंने कहा कि इस बात से भी इनकार किया कि पी.डब्लू.-1 ने उनके समक्ष कभी यह बयान नहीं दिया कि उनके भतीजे को हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, विकास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव और राजेश यादव ने पकड़ लिया था, जिसके बाद सोनू कुमार (पीड़ित) ने अपने दोस्त सुदामा कुमार और संतोष कुमार के साथ मिलकर शोर मचाया और उसके बाद भूषण यादव और राजेश यादव मोटरसाइकिल से सोनू कुमार को ले गए। उन्होंने यह भी कहा कि पी.डब्लू.-1 ने जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा नहीं किया। उन्होंने जिरह में आगे कहा कि सूचक/पी.डब्लू.-8 मनोहर साव ने जांच के दौरान यह बयान नहीं दिया कि जब वह रात 9:30 बजे साइकिल रेस समाप्त होने के बाद अपने घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि भूषण यादव और संतोष यादव उसके बेटे सोनू कुमार को ले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी

कहा कि अपने बयान में उन्होंने यह नहीं कहा कि पीड़ित को भूषण यादव ने पकड़ लिया था और अगली मोटरसाइकिल पर संतोष यादव और राजेश यादव थे, जिसके बाद वे जंगल की ओर चले गए। उन्होंने यह भी बयान दिया कि मुखबिर ने जांच के दौरान यह नहीं कहा कि उसने अपीलकर्ता-आरोपी का कुछ दूर तक पीछा किया था और जब वे वापस लौटे तो देखा नहीं गया। यह भी कहा गया कि मुखबिर ने जांच के दौरान अपने बयान में यह खुलासा नहीं किया कि घर आने के बाद उसने अपने भाई राजीव कुमार साव (पी.डब्लू.-1), दादी (पी.डब्लू.-4), पत्नी (पी.डब्लू.-6), मां (पी.डब्लू.-7) और बहनोई गौतम कुमार (जिनकी जांच नहीं की गई) को घटना के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पंकी देवी (पी.डब्लू.-6) ने उनके सामने जांच के दौरान यह नहीं बताया कि उसने देखा कि हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, विकास यादव, बिलाश यादव, उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी), सुधीर यादव सोनू कुमार (पीड़ित) को ले जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुतुल देवी (पीडब्लू-7) ने 07.11.02009 को यह बयान नहीं दिया कि आरोपी भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, किशन यादव, विकास यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) उसके घर आए और 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सभी अभियोजन पक्ष के गवाह, जिनके बयान उन्होंने जांच के दौरान दर्ज किए थे, घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। उन्होंने यह भी बयान दिया कि वर्तमान मामले के संबंध में कोई साइकिल या मोटरसाइकिल जब्त नहीं की गई। उन्होंने जांच के दौरान मुखबिर/पीडब्लू-8 और आरोपी व्यक्तियों के बीच भूमि विवाद के बारे में भी नहीं बताया।

35. सीडब्लू-1 संजीव कुमार है, जो मोबाइल नंबर 9504963018 का धारक प्रतीत होता है, जिससे फिरौती के लिए कॉल किया गया था। उसने बताया कि सिम उसकी मां रीता देवी के नाम पर है। बताया कि उक्त मोबाइल और सिम का इस्तेमाल

वह और उसकी मां कर रहे थे। बताया कि उक्त मोबाइल नंबर सह-आरोपी सुधीर यादव ने वर्ष 2009 में लिया था और उसके बाद उसे कभी वापस नहीं किया। उसने जांच के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर के समक्ष भी इस तथ्य का खुलासा किया। यह बयान अदालत के समक्ष भी दर्ज किया गया, जिसे उसने परीक्षण के दौरान पहचाना, जिसे पहचान करने पर प्रदर्श '1' के रूप में प्रदर्शित किया गया। उसने अदालत के समक्ष उदय यादव (अपीलकर्ता-आरोपी) की पहचान की। उन्होंने किसी भी अधिकारी/पुलिस के समक्ष इस तथ्य के बारे में कोई आवेदन नहीं किया कि उनका फोन उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) द्वारा लिया गया था। उन्होंने कंपनी से सिम कार्ड की सेवाएं बंद करने का अनुरोध भी नहीं किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके पास सिम कार्ड है, केवल अपराधियों की मदद करने के लिए उन्होंने फिरोती के लिए कॉल करने के लिए अपना मोबाइल दिया।

36. मौखिक साक्ष्यों की उपरोक्त चर्चाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचक पी.डब्लू.-8 ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है। उसने पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के समक्ष बयान दर्ज कराया। उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक लखीसराय को बयान देने से पहले ही उसे 5 लाख रुपए की फिरोती के लिए कॉल आ चुकी थी, लेकिन उसने इस अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम नहीं बताया। इसलिए, ट्रायल के दौरान इस अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम लेना पुलिस अधीक्षक लखीसराय के समक्ष दिए गए उसके लिखित बयान के विपरीत प्रतीत होता है, जिससे अपीलकर्ता-अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।

37. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान प्रथम सूचना प्रतिवेदन का आधार लखीसराय के पुलिस अधीक्षक के समक्ष दिया गया बयान है, जिसकी सुनवाई के दौरान जांच नहीं की गई और इसलिए, प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सामग्री को उसकी वास्तविक

भावना में साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुखबिर/पी.डब्लू.-8 ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को घटनास्थल पर नहीं देखा, जबकि पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-6 और पी.डब्लू.-7 ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को घटनास्थल पर मुखबिर के नाबालिग बेटे को पकड़ने के लिए नामित किया। पीडब्लू-7 जो मुखबिर के छोटे भाई की पत्नी है। राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) ने विशेष रूप से कहा कि अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा फोन पर फिरौती के लिए कॉल किए जाने के बाद सह-अभियुक्तों भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, किशन यादव, विकास यादव, राजेश यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) जिसमें सुधीर यादव भी शामिल हैं, द्वारा फिरौती के लिए सीधा कॉल किया गया था। पीडब्लू-6 द्वारा विशेष रूप से कहा गया कि सह-अभियुक्त भूषण यादव द्वारा घर पर फिरौती मांगी गई थी। फिरौती की मांग के संबंध में यह महत्वपूर्ण पहलू जो अपीलकर्ता-अभियुक्त की सजा का एकमात्र आधार प्रतीत होता है, न तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन के माध्यम से उठाया गया था और न ही मुखबिर या किसी अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा परीक्षण के दौरान कहा गया था, जिससे इस अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा फिरौती की मांग के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।

38. प्रभारी अधिकारी के बयान से जो प्रतीत होता है, वह स्वीकार्य स्थिति है। (पीडब्लू-10) कि जांच के दौरान सिम सहित कोई भी मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया, जैसा कि फिरौती मांगने में शामिल होने का दावा किया गया था, जो कि कथित तथ्य की पुष्टि करता है। मोबाइल और सिम की जब्ती न होना और इस संबंध में किसी भी कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) की उपलब्धता भी गंभीर है। अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा फिरौती के लिए की गई कॉल के बारे में संदेह जताया गया। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मोबाइल नंबर 9504963018, जिसका कथित तौर पर 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया था, संजीव कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल

किया जा रहा था, जिसकी जांच सीडब्ल्यू-1 के रूप में की गई और जिसका बयान भी धारा 164 आ.दं.सं के तहत दर्ज किया गया था। उक्त सिम उसकी मां रीता देवी के नाम पर थी। उसने मुकदमे के दौरान कहा और स्वीकार किया कि उसका फोन सह-अभियुक्त सुधीर यादव ने 2009 के 11वें महीने में लिया था। अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान कोई सबूत सामने नहीं आया कि उक्त सिम किसी भी समय अपीलकर्ता-अभियुक्त के पास थी। इसके अलावा, पीडब्लू-8 द्वारा अभिलेख किया गया और पीडब्लू-10 के समक्ष प्रदर्शित किया गया ऑडियो किसी फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था जिस मोबाइल नंबर पर फिरौती के लिए कॉल आया था, यानी 9631146123, वह मुखबिर का नहीं है, बल्कि पीडब्लू-1 राजीव कुमार साओ का है।

39. इस संदर्भ में, **टॉमसो ब्रूनो** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा **25 और 26** को फिर से प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"25. वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का उत्पादन" साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष के लिए बहुत मददगार है। **मोहम्मद अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2012) 9 एससीसी 1: (2012) 3 एससीसी (क्रि) 481]** के प्रकाश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रासंगिकता भी स्पष्ट है, जिसमें इंटरनेट लेनदेन की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने से अभियोजन पक्ष को अभियुक्तों के अपराध को साबित करने में बहुत मदद मिली। इसी तरह, **राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू [(2005) 11 एससीसी 600 2005 एससीसी (क्रि) 1715]** में, मारे गए आतंकवादियों और हमले के मास्टरमाइंड के बीच

संबंध केवल मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्राप्त फोन कॉल प्रतिलेखों के माध्यम से स्थापित किए गए थे।

26. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीसीटीवी फुटेज का संग्रह न करना, साइट प्लान का अधूरा होना, सभी अभिलेख और आरोपियों से जब्त मोबाइल फोन के सिम विवरण को शामिल न करना दोषपूर्ण जांच के उदाहरण हैं और इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीसीटीवी फुटेज का उत्पादन न करना, कॉल अभिलेख (विवरण) का संग्रह न करना और आरोपियों से जब्त मोबाइल फोन के सिम विवरण को केवल दोषपूर्ण जांच के उदाहरण नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह सर्वोत्तम साक्ष्य को रोकने के बराबर है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं उठाया जा सका या सीडी कॉपी नहीं बनाई जा सकी।"

40. उपर्युक्त परिस्थितियों में, अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा मोबाइल नंबर से मुखबिर/पीडब्लू-8 को फिरौती कॉल 9504963018. करने से जोड़ना विश्वसनीय नहीं लगता।

41. यह भी कहना है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी यह खुलासा नहीं किया गया है कि मुखबिर या अभियोजन पक्ष का कोई गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। प्रभारी अधिकारी/पीडब्लू-10 ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि घटना के बारे में कई सुधारित संस्करण, जिसके लिए विद्वान बचाव पक्ष के वकील ने मुकदमे के दौरान ध्यान आकर्षित किया था, जिसे प्रभारी अधिकारी/पी.डब्लू.-10 के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने आ.दं.सं की धारा 161 के तहत जांच के दौरान बयान दर्ज किया और जिरह के दौरान विशेष रूप से इनकार किया, कि पी.डब्लू.-1 ने उनके सामने कभी यह बयान नहीं दिया

कि उनके भतीजे को हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, विकास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव और राजेश यादव ने पकड़ लिया था, जिसके बाद सोनू कुमार (पीड़ित) ने अपने दोस्त सुदामा कुमार और संतोष कुमार के साथ मिलकर शोर मचाया और उसके बाद भूषण यादव और राजेश यादव ने सोनू कुमार को मोटरसाइकिल से ले गए। उन्होंने यह भी कहा कि पी.डब्लू.-1 ने जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शी के रूप में दावा नहीं किया। उन्होंने जिरह में आगे कहा कि मुखबिर/पीडब्लू-8 मनोहर साव ने जांच के दौरान यह बयान नहीं दिया कि जब वह रात 9:30 बजे साइकिल रेस खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहा था, तो उसने भूषण यादव और संतोष यादव को उसके बेटे सोनू कुमार को ले जाते हुए देखा था। उसने यह भी कहा कि अपने दोबारा बयान में उसने यह नहीं कहा कि पीड़िता को भूषण यादव ने पकड़ लिया था और अगली मोटरसाइकिल पर संतोष यादव और राजेश यादव थे, जिसके बाद वे जंगल की ओर चले गए। उन्होंने यह भी बयान दिया कि मुखबिर ने जांच के दौरान यह नहीं बताया कि उसने अपीलकर्ता-आरोपी का कुछ दूर तक पीछा किया था और जब वे नज़र से ओझल हो गए, तभी वापस लौटा। यह भी कहा गया कि मुखबिर ने जांच के दौरान अपने बयान में यह नहीं बताया कि घर आने के बाद उसने अपने परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पिकी देवी (पी.डब्लू.-6) ने उनके समक्ष जांच के दौरान कहा है कि उसने देखा कि उदय यादव (अपीलकर्ता आरोपी) सहित आरोपी सोनू कुमार (पीड़ित) को ले जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुतुल देवी (पीडब्लू-7) ने 07.11.2009 को यह बयान नहीं दिया कि आरोपी भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, किशन यादव, विकास यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) उसके घर आए और 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सभी अभियोजन पक्ष के गवाह, जिनका बयान उन्होंने जांच के

दौरान दर्ज किया था, वे मामले के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान मामले के संबंध में कोई साइकिल या मोटरसाइकिल जब्त नहीं की गई। उन्होंने जांच के दौरान सूचक/पीडब्लू-8 और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि विवाद के बारे में भी जानकारी नहीं दी।

42. उपरोक्त चर्चित विरोधाभास और सुधार यह सुझाव नहीं देते हैं कि यह मामूली विरोधाभास का मामला है, बल्कि यह सुझाव देते हैं कि यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन के माध्यम से लगाए गए आरोपों से पूरी तरह से सुधार है। जांच के दौरान प्रभारी अधिकारी/पीडब्लू-10 द्वारा ऐसा कोई बयान देने से इनकार करना, जैसा कि पूर्वोक्त है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 155(3) के अनुसार अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है और उनकी गवाही अपीलकर्ता-अभियुक्त को शामिल करने के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रतीत नहीं होती है।

43. संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, कृष्णागिरि के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 21, 22 और 23 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जिसकी रिपोर्ट (2012) 4 एससीसी 124 में दी गई थी, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:

“21. नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2000) 8 एससीसी 457: 2000 एससीसी (क्रि) 1546: एआईआर 2000 एससी 3352] में इस न्यायालय ने यह माना कि गवाह की गवाही में विसंगतियां जो स्मृति चूक के कारण हो सकती हैं, स्वीकार्य थीं, गवाही में विरोधाभास स्वीकार्य नहीं थे। इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एससीसी डी. 483, पैरा 42)

"42. केवल ऐसी चूकें जो भौतिक विवरणों में विरोधाभास के बराबर हों, गवाह की गवाही को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। पुलिस के बयान में चूक अपने आप में जरूरी नहीं कि गवाह की गवाही को अविश्वसनीय बना दे। जब गवाह द्वारा न्यायालय में दिया गया संस्करण उसके पहले के बयानों में बताए गए विवरणों से भौतिक विवरणों में भिन्न होता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है, अन्यथा नहीं। सच्चे गवाहों के बयानों में छोटे-मोटे विरोधाभास दिखाई देने ही चाहिए क्योंकि स्मृति कभी-कभी गलत हो जाती है और अवलोकन की भावना व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है।"

22. विसंगतियों और विरोधाभासों के बीच अंतर को इस न्यायालय ने *हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज* [(2000) 1 एससीसी 247: 2000 एससीसी (सीआरआई) 147: एआईआर 1999 एससी 3916] में स्पष्ट किया था। *हरियाणा राज्य बनाम गुरदयाल सिंह* [(1974) 4 एससीसी 494: 1974 एससीसी (सीआरएल) 530: एआईआर 1974 एससी 1871] में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ भी लिया जा सकता है, जहां अभियोजन पक्ष के गवाह ने घटना के दो असंगत संस्करण प्रस्तुत किए थे। इनमें से एक संस्करण न्यायालय में दिया गया था, जबकि दूसरा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में शामिल था। इस न्यायालय ने माना कि ये विरोधाभासी संस्करण थे, जिनके आधार पर तथ्य का निष्कर्ष सुरक्षित रूप से नहीं निकाला जा सकता था।

23. इस न्यायालय ने *गुरदयाल सिंह* [(1974) 4 एससीसी 494: 1974 एससीसी (क्रि) 530 एआईआर 1974 एससी 1871] में टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 500, पैरा 21)

"21. वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों ने घटना के दो असंगत संस्करण प्रस्तुत किए हैं। घटना का एक संस्करण अदालत में गवाहों के साक्ष्य में निहित है, जबकि दूसरा संस्करण पुलिस के समक्ष उनके बयानों में निहित है। इन विरोधाभासी संस्करणों को देखते हुए, उच्च न्यायालय, हमारी राय में, इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुंचा है कि अभियुक्त की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

44. वर्तमान मामले में, बेशक प्रथम सूचना प्रतिवेदन घटना के पांच दिन बाद दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-3, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 ने भूमि विवाद और आरोपी व्यक्तियों के साथ शत्रुतापूर्ण शर्तों के बारे में विशेष रूप से बताया। इसलिए, देरी से दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है। नंद लाल मामले (सुप्रा) के मामले में निर्णय के पैरा '31' को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा।

31. जैसा कि इस न्यायालय ने रमेश बाबूराव बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2007) 13 एससीसी 501] में माना है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक मूल्यवान साक्ष्य है, हालांकि यह पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकता है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन का तत्काल दर्ज होना व्यक्तियों की संख्या के बारे में संदेह को दूर करता है, खासकर जब मामला दो समूहों के बीच लड़ाई से जुड़ा हो। जब पक्ष आपस में झगड़ रहे हों, तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन का तत्काल दर्ज होना अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता प्रदान करता है।"

45. वर्तमान मामले में, पीडब्लू-8/सूचनाकर्ता के बयान से यह प्रतीत होता है कि उसने अपीलकर्ता-अभियुक्त को घटनास्थल पर नहीं देखा था और जब वह प्रारंभिक

खोज के बाद घर लौटा, तो उसने अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी पीडब्लू-1, पीडब्लू-4, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 और अन्य परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में बताया। लेकिन इन सभी गवाहों ने मुकदमे के दौरान खुद को घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया। ये गवाह पीड़ित के माता-पिता/निकटतम रिश्तेदार हैं जो परिवार के सदस्य हैं। भूमि विवाद/पड़ोस विवाद की स्थिति स्वीकार की गई है। इसलिए, परिस्थितियों में, अपीलकर्ता-अभियुक्त के हितबद्ध गवाह होने के उनके कथन को स्वीकार करना असुरक्षित है, ताकि अभियोजन पक्ष के मामले से अलग हटकर अपीलकर्ता-अभियुक्त को किसी भी तरह से दोषी ठहराया जा सके।

46. मुखबिर/पी.डब्लू.-8 और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के अनुसार, जो घटनास्थल पर तुरंत आए थे, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि लगभग 200 लोगों की भीड़ थी, जिनमें से अधिकांश सह-ग्रामीण और आस-पास के क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन इस मामले में किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र स्वतंत्र गवाह पी.डब्लू.-3 राम रजक हैं, अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषिता को जोड़ने के लिए परीक्षण के दौरान कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा और कहा कि उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष कोई बयान नहीं दिया और न ही घटनास्थल का दौरा किया। **सरवनन** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा '14' को फिर से प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"14. यह सिद्धांत कि गवाह करीबी रिश्तेदार हैं और परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण गवाह होने के कारण, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1953 में दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1953) 2 एससीसी 36: एआईआर

1953 एससी 364] में निरस्त कर दिया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया था: (एआईआर पी. 366, पैरा 26)।

26. एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आए जो दागी होने की संभावना है और इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि जब तक गवाह के पास आरोपी के खिलाफ दुश्मनी जैसे कारण न हों, जिससे उसे झूठा फंसाया जा सके। आम तौर पर एक करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को पर्दा डालने और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला आखिरी व्यक्ति होगा। यह सच है कि जब भावनाएँ प्रबल होती हैं और दुश्मनी के लिए व्यक्तिगत कारण होते हैं, तो एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी के साथ घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ गवाह की कोई दुश्मनी होती है, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार तैयार किया जाना चाहिए और केवल संबंध का तथ्य आधार होने से कहीं दूर अक्सर सत्य की गारंटी होती है। हालाँकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का न्याय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे अवलोकन केवल उन मामलों का मुकाबला करने के लिए किए गए हैं जो अक्सर हमारे सामने विवेक के सामान्य नियम के रूप में सामने रखे जाते हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए तथा उसके द्वारा शासित होना चाहिए।"

47. तथ्यों तथा परिस्थितियों के मद्देनजर, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषसिद्धि तथा सजा को कानून की नजर में टिकाऊ नहीं कहा जा सकता।

48. तदनुसार, संदेह का लाभ देते हुए, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता-अभियुक्त को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उत्तर देने में विफल रहा है, इसलिए, दिनांक 03.05.2019 को विद्वान त्वरित न्यायालय-II, व्यवहार न्यायालय, लखीसराय में सत्र परीक्षण संख्या 494 ए/2011/परीक्षण संख्या 326/2018, जो लखीसराय थाना कांड संख्या 565/2009 जी.आर. कांड संख्या 1226/2009 से उत्पन्न हुआ है, द्वारा दोषसिद्धि तथा सजा के आदेश का विवादित निर्णय पारित किया गया। को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

49. अपीलकर्ता-आरोपी, अर्थात् उदय यादव को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

50. अपील स्वीकार की जाती है।

51. इस फैसले की एक प्रति ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ विद्वान ट्रायल कोर्ट को तुरंत भेजी जाए।

(अंजनी कुमार शरण, न्यायामूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायामूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्कलेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।